वर्ष: 02 अंक: 06

आज़ादी का अमृत महोत्सव

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
सत्यमेव जयते
GOVT OF INDIA
NCSC

आयोग की मासिक पत्रिका

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूज़लेटर - नवंबर - 2022

National Commission For Scheduled Castes
5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग न्यूजलेटर

वर्ष: 02 अंक: 06 नवंबर 2022

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com

@srajeshranjan

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी मासिक पत्रिका के जरिए लोगों तक अहम जानकारियां पहुंचाने का काम लगातार कर रहा है। आयोग अभी तक सफलतापूर्वक सत्रह अंक प्रकाशित कर चुका है। यह अठारहवां अंक होगा। इस अंक में हमने आयोग द्वारा अनुसूचित जाति आरक्षण नीति का कार्यान्वयन के लिए समीक्षा बैठक, राज्य कार्यालयों में मामलों की सुनवाई, मुख्यालय में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों, गंभीर मामलों में स्थलीय निरीक्षण, सोशल मीडिया के जरिए अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होने वाली घटनाओं पर मांगी गई रिपोर्ट को शामिल किया है। आयोग की कोशिश है कि इन सभी मामलों की जानकारी आम लोगों तक भी पहुंचती रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए मासिक पत्रिका का प्रकाशन जारी है। आपका यह सहयोग आगे भी मिलते रहे, इसकी हम अपेक्षा करते हैं।

धन्यवाद

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes

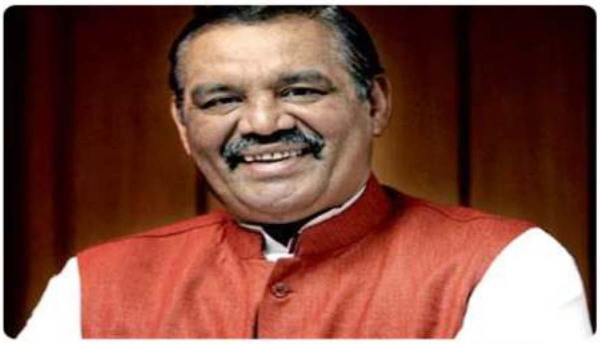

SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN

SHRI ARUN HALDER
VICE CHAIRMAN

DR. ANJU BALA
MEMBER

SHRI SUBHASH RAMNATH PARDHI
MEMBER

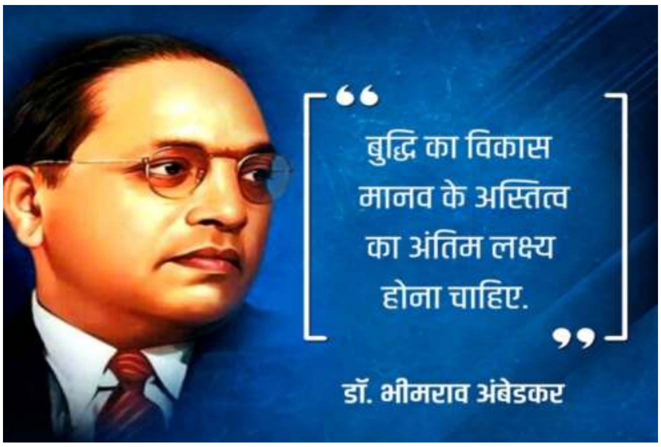

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

माननीय अध्यक्ष का संदेश

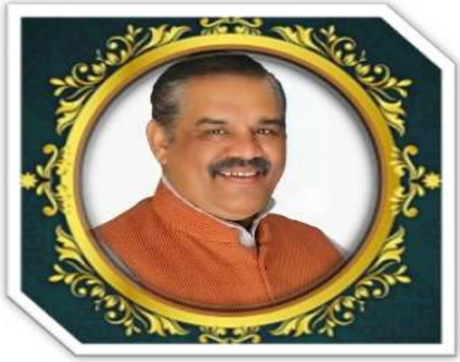

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के अठारहवें अंक के विमोचन के लिए यह संदेश लिखते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। आयोग द्वारा अभी तक मासिक पत्रिका के 17 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित किए जा चुके हैं। आयोग द्वारा प्रकाशित यह मासिक पत्रिका आम लोगों तक आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों को पहुंचाने में अहम भूमिका का निर्वहन कर रही है।

बीते माह 23 नवंबर 2022 को आयोग की आठवीं आधिकारिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आयोग के सभी माननीय सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में आयोग से संबंधित कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई फैसले भी लिए गए।

नवंबर माह के दौरान ही आयोग ने एचपीसीएल, कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जैसी संस्थाओं की समीक्षा बैठक की। साथ ही बिहार राज्य के कई प्रमंडलों में जाकर भी समीक्षा बैठक कर आरक्षण नीति की स्थिति की जांच की। इतना ही नहीं, आयोग द्वारा लगातार अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में स्थलीय निरीक्षण से लेकर आयोग मुख्यालय में जनसुनवाई और सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

सोशल मीडिया के माध्यम से मिली घटनाओं की जानकारी पर भी संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग समाज के हाशिये पर खड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग का प्रयास रहता है कि दूरस्थ गांव से लेकर शहर तक के प्रत्येक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या अन्याय न होने पाए।

आयोग का प्रयास रहेगा कि मासिक पत्रिका के जरिए आपको जानकारी मिलती रहे। इसके लिए आशा है कि आपका सहयोग मिलता रहेगा।

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

विजय सांपला

अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

आयोग की 8वीं बैठक

छठे आयोग का गठन फरवरी 2021 में किया गया था। गठन के बाद से अभी तक आयोग की आठ बैठकें हो चुकी हैं। 23 नवंबर 2022 को आठवीं बैठक हुई।

यह बैठक नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी ने की।

इस दौरान माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार, माननीय सदस्या डॉ अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी मौजूद रहे।

सचिव श्रीमती उपमा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, डीआईजी श्रीमती सन्मीत कौर, उपसचिव श्री संदेश सक्सेना, निदेशक श्री कौशल कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में आयोग के काम को लेकर चर्चा की गई।

समीक्षा बैठक

HPCL की समीक्षा बैठक

छठे आयोग का गठन फरवरी 2021 में किया गया था। गठन के बाद से अभी तक आयोग की आठ बैठकें हो चुकी हैं। 23 नवंबर 2022 को आठवीं बैठक हुई।

यह बैठक नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी ने की।

इस दौरान माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार, माननीय सदस्या डॉ अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी मौजूद रहे।

सचिव श्रीमती उपमा श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, डीआईजी श्रीमती सन्मीत कौर, उपसचिव श्री संदेश सक्सेना, निदेशक श्री कौशल कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में आयोग के काम को लेकर चर्चा की गई।

कोचीन पोर्ट-शिपयार्ड की समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने केरल राज्य का आधिकारिक दौरा किया। यह दौरा माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने नेतृत्व में किया गया। इस दौरान केरल स्थित कोची में आयोग द्वारा कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण (कोचीन पोर्ट अथॉरिटी) और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की समीक्षा बैठक की गई।

इस दौरान आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला और माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी भी उपस्थित रहे। इस समीक्षा बैठक में आयोग के निदेशक श्री कौशल कुमार और कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष व उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान आयोग ने कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में अनुसूचित जाति वर्ग कल्याण हेतु विस्तार से चर्चा की गई।

सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 लोगों की मौत, आयोग का स्थलीय निरीक्षण

तमिलनाडु के करूर जिले के गांधी नगर इलाके में निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आकर चार सफाई कर्मियों की मौत संबंधी खबरों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया। आयोग के एक दल ने माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार की अगुवाई में मामले की गंभीरता को समझते हुए स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जिला कलक्टर से अनुसूचित जाति के परिवारों को श्रम अधिनियम के तहत 5 लाख अनुदान देने की संस्तुति की। साथ ही जिला प्रशासन को सलाह दी कि सीवर में वाली मौतों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें क्योंकि यह तमिलनाडु राज्य में दो महीने के भीतर दूसरी सीवर मौत आपदा है। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ जांचकर न्यायोचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

बिहार राज्य में समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने बिहार राज्य में समीक्षा बैठक के लिए दौरा किया। इस दल की अगुवाई माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने की। सारण प्रमंडल की समीक्षा के लिये छपरा में आयोजित बैठक में प्रमंडल आयुक्त, आईजी, जिलाधिकारी, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक सहित जनपद के अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाओं एवं व्यवस्थाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। माननीय सदस्या बिहार राज्य के दौरे के दौरान सुपौल जिले के भगवानपुर गांव पहुंची। वहां पर उन्होंने गांव की स्थिति के बारे में ग्रामवासियों से वार्ता की। साथ ही गांव का निरीक्षण कर शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के विषय में आंगनबाड़ी और पंचायत मुखिया से जानकारी प्राप्त कीI

लोगों ने बताई अपनी समस्याएं

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राज्य कार्यालय में आए लोगों के साथ अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक की। इस बैठक में उन्होंने लोगों से उनकी समस्याओं को जाना। माननीय उपाध्यक्ष ने समस्याओं को दूर कराने के लिए भरोसा दिलाया। इस दौरान तेलंगाना सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

कोशी प्रमंडल , सहरसा में समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने बिहार के कोशी प्रमंडल, सहरसा में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस समीक्षा बैठक के दौरान जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की समस्याओं एवं उनके समाधान करने हेतु निर्देशित किया।

HPCL विशाख की समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक दल ने आंध्र प्रदेश का आधिकारिक दौरा किया। आयोग ने यहां पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विशाखापट्टनम रिफाइनरी की समीक्षा बैठक की। यह समीक्षा बैठक माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी की अगुवाई में की गई। इस दौरान रिफाइनरी व आयोग के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। यहां पर रिफाइनरी में कार्यरत अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बनाई गई आरक्षण नीति की समीक्षा की गई।

खबरों में आयोग

राष्ट्रीय राज्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक खेल अपराध कानून मनोरंजन विविध

| राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य ने प्रमंडल स्तरीय समीक्ष

19 Nov 2022 18:28:07

सहरसा,19 नवंबर (हि.स.)। भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉ अ अध्यक्षता में शनिवार को अनुसूचित जाति के लिए संचालित सभी प्रकार की योजनाएं एवं पुलिस सं प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक स्थानीय विकास भवन सभागार में किया गया। कोशी प्रमंडलीय चादर और बुके देकर सम्मानित किया गया। बैठक में कोशी प्रमंडल अन्तर्गत सहरसा,सुपौल,मधे पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता सिविल सर्जन,जिला शिक्षा पदा कल्याण पदाधिकारी, लीड बैंक के प्रतिनिधि एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। सर्वप्रथम शि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालयों में नामांकन एवं छात्रवृति की स्थिति के बारे में बताया ग विद्यालय में छात्रों के नामांकन में जो बच्चे छूट गये हैं उसे अभियान चलाकर शामिल करने का निर्देश आयोग को समर्पित डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखने का निर्देश दि अलावे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं की प्रगति,जननी सुरक्षा योजना, कार्ड,मुद्रा लोन, उज्वला योजना,भूमिहीन परिवारों के लिए आवास हेतु जमीन उपलब्धता,जिले में जिलावार विस्तृत समीक्षा की गई। जिसमे उपलब्धि संतोषजनक पाया गया।बैठक को संबोधित सदस्या द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों तक विधि प्रावधान एवं संचालित लोक कल्याणकारी ससमय सुलभ कराने को लेकर कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

स्वास्थ्य विभाग के सभी सिविल सर्जन को उक्त समुदाय बाहुल्य क्षेत्रों में साकारात्मक कार्यक्रम योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया।आज के परिवेश में इस सम् पदाधिकारियों को अपने व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति अत्या अधिकार अधिनियम के लंबित मामलों का निष्पादन समय पर हो, इसके लिए सभी जिला पदाधिका अधीक्षक को निगरानी करने का निर्देश दिया गया।आयुक्त कोशी प्रमंडल गोरखनाथ द्वारा सभी पदा निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति के लिए संचालित सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत निष्पादन स सुनिश्चित करेंगे।

समीक्षा बैठक: बेटियों की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण व शिक्षा पर जोर आयोग का मुख्य फोकस

सहरसा 8 दिन पहले

बैठक में समीक्षा करती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉ अंजू बाला।

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य ने प्रमंडल के सभी अधिकारियों के साथ की समीक्षा
- अनुसूचित जाति के लिए जितनी राशि व्यय हुई उसकी रिपोर्ट आयोग को भेजें

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉ अंजू बाला ने बेटियों की सुरक्षा, अपराध पर नियंत्रण और शिक्षा पर बल देते हुए अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि संगीन मामले में निष्पक्षता से केस का निष्पादन करें। जब मामला कमीशन तक आ गया तो फिर उसकी जांच करा कर दोषी पर कड़ी कार्रवाई होगी। शनिवार को विकास भवन में तीन जिलों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद आयोग उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सहरसा की रिपोर्ट हमने देखी है। अच्छा काम हो रहा है। खासकर शिक्षा, बैंक लोन आदि रिपोर्ट संतोषजनक है। क्राईम केसों का डिस्पोजल भी ठीक ही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा समर्पित रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। फिर पुरा कमीशन जब आएगा तब फिर से समीक्षा होगी। स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में आयोग की सदस्या ने कहा कि हत्या, रेप, शिक्षा, सुरक्षा के मामले में क्या कार्रवाई हुई, मुआवजा मिला या नहीं, इन सब बातों की समीक्षा की जा रही है। बहुत सारी बातें सामने आई है। कई कमियां भी उजागर हुई है। मेरी राय है कि मामले को जिले से बाहर न जाने दें, क्योंकि आयोग में बात आएगी तो कमीशन उसे छोड़ने वाला नहीं है। खासकर शिक्षा, ऋण वगैरह के कई मामले आए जिसको लेकर 15 दिनों का समय रिपोर्ट के लिए दिया गया है। उन्होंने बातचीत में कहा कि सहरसा की स्थित संतोषजनक है। जिसका अन्य जिलों को अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर आयोग का फोकस है और बाबा साहब का सपना भी शिक्षा से ही शुरू होता है। चाहे खाना कम खाएँ लेकिन बच्चों को शिक्षा अवश्य दें। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है इस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। क्राइम बढ़ रहा है इसके लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

पीएम आवास योजना, स्वास्थ्य योजनाओं की ली जानकारी

इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,भारत सरकार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति के लिए संचालित सभी प्रकार की योजनाएं एवं पुलिस संबंधी कार्यों की प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक की गई। उक्त बैठक में कोसी प्रमंडल के आयुक्त गोरखनाथ के साथ सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के डीएम, एसपी, डीडीसी, अपर समाहर्ता, सीएमन, डीईओ, जिला कल्याण पदाधिकारी, लीड बैंक के प्रतिनिधि एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। सर्वप्रथमडीईओ ने विद्यालयों में नामांकन एवं छात्रवृत्ति की स्थिति के बारे में बताया। साथ ही विद्यालय में छात्रों के नामांकन में जो बच्चे छूट गए थे उसे अभियान चलाकर शामिल करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं की प्रगति, जननी सुरक्षा योजना, मनरेगा जॉब कार्ड,मुद्रा लोन, उज्ज्वला योजना, भूमिहीन परिवारों के लिए आवास हेतु जमीन उपलब्धता, जिले में छात्रावासों की जिला वार विस्तृत विस्तृत समीक्षा की गई।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कहा, जरुरत पड़ने पर बंगाल के जेल मंत्री को भी किया जा सकता है गिरफ्तार

JAGRAN NEWS
Publish Date: Tue, 15 Nov 2022 08:56 PM (IST)
Updated Date: Tue, 15 Nov 2022 08:56 PM (IST)

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पर अश्लील टिप्पणी करने के मामले में बोले आयोग के उपाध्यक्ष। अखिल गिरि के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 100 से ज्यादा शिकायतें जमा पड़ी हैं जिनके आधार पर उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। ठीक तरीके से जवाब नहीं देने पर समन भेज जाएगा।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु प अश्लील टिप्पणी करने के मामले में जरुरत पड़ने पर बंगाल के जेल मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व तृणमूल कांग्रेस विधायक अखिल गि को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अखिल गिरि के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में 100 से ज्या शिकायतें जमा पड़ी हैं, जिनके आधार पर उन्हें नोटिस भेजा जाएगा।

अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें : डॉ अंजू बाला

छपरा कार्यालय (एसएनबी)। सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली, डॉ अंजू बाला की अध्यक्षता में विधि प्रावधान के अनुरूप सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धि को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन समाहरणालय सारण के सभागार में आयोजित की गई।

बैठक में संजय कुमार सिंह निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पुलिस उपमहानिरीक्षक, सारण प्रमंडल तथा सारण, सीवान, गोपालगंज जिले के जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, सारण, अपर समाहर्ता, सारण, तीनों जिला के पुलिस उपाधीक्षक, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन एवं अन्य संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक में सारण प्रमंडल अंतर्गत जिला सारण, सीवान एवं गोपालगंज जिले के डीएम,एसपी, डीडीसी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, लीड बैंक के प्रतिनिधि एवं संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा भाग लिया गया। माननीय सदस्या डॉ मंजू बाला के द्वारा जिलावार अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा के तहत शिक्षा विभाग के जरिए विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं छात्रवृत्ति दिए जाने की अद्यतन स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं की प्रगति, मनरेगा जॉब कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, मुद्रा लोन, उज्ज्वला योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, भूमिहीन परिवारों के लिए आवास हेतु जमीन की उपलब्धता, जिले में छात्रावासों की स्थिति तथा लोक अभियोजक के कार्यों एवं उपलब्धियों की वित्तीय वर्ष

संबोधित करती डॉ. अंजू बाला।

2019-20 से 2021- 22 तक की जिलावार गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान एवं संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी गणों को कार्य में और अधिक प्रगति लाने का निर्देश दिया गया है।

बैठक को संबोधित करते हुए सदस्य महोदया द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्तियों तक विधि प्रावधान के अनुरूप संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं को ससमय सुलभ कराने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश एवं सुझाव दिया गया। सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति समुदाय के बहुल्य क्षेत्रों में सकारात्मक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों में जागरूकता लाएं। जरूरतमंद लोगों को सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ समय पर दें।

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि विद्यालय में लक्ष्य के अनुरूप छात्र-छात्राओं के नामांकन कराने हेतु अभियान चलावे। समर्पित डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो इसका पूरा पूरा ध्यान रखने को कहा गया। विद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों में बच्चों के साथ उत्तम व्यवहार करने की जरूरत पर बल दिया गया। छात्रवृत्ति देने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। समुदाय के विकास के लिए सकारात्मक सोच और मेहनत की जरूरत है।

अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिकार अधिनियम के तहत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। अनुसूचित जाति समुदाय के पीड़ित परिवारों को नियमानुसार मुआवजे की राशि समय पर सुलभ हो इसे सुनिश्चित करने का कहा गया।

अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिकार अधिनियम के लंबित मामलों का निष्पादन समय पर हो। इसके लिए संबंधित डीएम एवं एसपी को मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। यदि इस समुदाय के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की अत्याचार एवं असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जाती है तो वरीय पदाधिकारियों को शीघ्र घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों को सांत्वना एवं न्याय उचित कार्रवाई करने को कहा गया।

अनुसूचित समुदाय के योग्य व्यक्ति अगर सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए कार्यालय अथवा बैंक आते हैं तो उन्हें सही मार्गदर्शन देने के साथ योजना का लाभ देने को कहा गया। ताकि उन्हें बार-बार नाहक परेशानी उठाना नहीं पड़े। लीड बैंक के सभी प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि अपने-अपने जिला के सभी बैंकों के लक्ष्य के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण उपलब्ध करा सुनिश्चित करें ताकि वह अपना रोजगार का सृजन कर सकें।

आयुक्त सारण प्रमंडल, पूनम द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति के लिए संचालित योजनाओं का शत प्रतिशत निष्पादन समय पर सुनिश्चित करें।

खबरों में आयोग

कहा- समय पर पूरा करें अनुसूचित जाति के विकास और कल्याण की योजनाएं

संवाददाता, छपरा (सदर)

अनुसूचित जाति की विभिन्न योजना की समीक्षा करती राष्ट्रीय आयोग के सदस्य.

सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विकास एवं कल्याण के लिए चलायी जाने वाली योजनाओं का कार्यान्वयन आपसी समन्वय से ससमय करें. यह निर्देश राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सदस्य डॉ अंजु बाला ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को दिये. उन्होंने जिलावार अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम की समीक्षा के तहत शिक्षा विभाग के जरिये विद्यालय में छात्र-छात्राओं के नामांकन, छात्रवृति दिये जाने की अद्यतन स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की प्रगति, मनरेगा जॉब कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, मुद्रालोन, उज्जवला योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना, भूमिहीन परिवारों के लिए आवास हेत जमीन की उपलब्धता को पूरा करें. उन्होंने जिले में छात्रावासों की स्थिति तथा जिलावार लोक अभियोजक वित्तीय वर्ष 2019-20 से लेकर 21-22 तक की उपलब्धियों एवं कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अनुसूचित जाति समुदाय के व्यक्तियों तक विधि प्रावधान के अनुरूप संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं को ससमय सुलभ कराने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश एवं सुझाव दिया. बैठक में सिविल सर्जन को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति समुदाय के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में सकारात्मक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों में जागरूकता लाये. जरूरतमंद लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ ससमय दे.

विद्यालय में लक्ष्य के अनुरूप नामांकन हेतु अभियान चलाये डीइओ : बैठक में डॉ अंजु बाला ने सारण, सीवान व गोपालगंज के डीइओ को निर्देश दिया कि विद्यालयों में लक्ष्य के अनुरूप एससी के छात्र-छात्राओं के नामांकन हेतु अभियान चलाये. इस संबंध में तैयार डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये. उन्होंने इस वर्ग के बच्चों की साथ शिक्षण संस्थानों में उत्तम व्यवहार किये जाने की जरूरत जताते हुए बिना किसी परेशानी के छात्रवृति भुगतान की जरूरत जतायी. उन्होंने कहा कि अनुसूचितजाति अत्याचार अधिनियम के तहत त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाये तथा समुदाय के पीड़ित को नियमानुसार मुआवजा ससमय दिलाया जाये. बैठक में डीएम तथा एसपी को उन्होंने अनुसूचित जाति के योजनाओं की मॉनेटरिंग करने की जरूरत जताते हुए किसी भी प्रकार के अत्याचार एवं असामाजिक तत्वों द्वारा पहुंचाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षति की स्थिति में वरीय पदाधिकारियों को शीघ्र घटना स्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. लीड बैंक को निर्देशित किया कि योग्य आवेदकों को ससमय योजना का लाभ संवेदनशील होकर उपलब्ध करायें. बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त पूनम ने भी सभी योजनाओं के शत प्रतिशत निष्पादन का निर्देश देते हुए लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के निदेशक संजय सिंह, डीआइजी सारण पी कन्नन, डीएम राजेश मीणा, सीवान व गोपालगंज के डीएम एसपी, डीडीसी अपर समहर्ता, जिला कल्याण पदाधिकारी आदि विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.

भगवानपुर पंचायत में अनुसूचित जाति से मिल कहा, अनुसूचित जाति के प्रत्येक लोगो को सरकार की योजनाओं का सही से नहीं मिल रहा लाभ : अंजू बाला

दैनिक मेंशन एजेंड 308-1/3

आश नारायण मिश्रा, वीरपुर (सुपौल)। बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत भगवानपुर पंचायत वार्ड 06 में रविवार को अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग दिल्ली के सदस्य अंजू बाला अपनी वीरपुर भ्रमण दौरान पहुँची। जहाँ मुखिया देवेंद्र दास ने सदस्य व सेक्रेटरी को गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया। वहीं अंजू बाला ने पंचायत के वार्ड 6 अनुसूचित जाति क्षेत्र में पैदल मार्च करते हुए लोगों की समस्या को सुना। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की हर योजनाओं पर विशेष चर्चा की ग। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से मिल रही लाभ से सम्बंधित जानकारी भी ली। जिसके साथ अनुमंडल व प्रखंड स्तरीय सभी अधिकारी व भीमनगर ओपी पुलिस भी मौजूद थे।

जानकारी देते हुए अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग के सदस्य अंजू बाला ने कहा कि डिवीजन वार रिव्यू किया जा रहा है। इसको लेकर गांव में पहुंचकर अनुसूचित जाति के लोग कैसे रह रहे हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ मिल रही है या नहीं। योजनाओं का इंप्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं। कहा कि गांव के विजिट करने के दौरान पाया गया कि सड़के एवं आवास अच्छी है, लेकिन अनुसूचित जाति समुदाय के लोग के बच्चों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण से वंचित हो रहे है। बहुत सारे बच्चे ऐसे है जो स्कूल जाने में एवं शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफी इंटरेस्टेड है, लेकिन उन्हें कोई माध्यम और सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है। जिसकी वजह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हो रहे है। वहीं कहा कि स्थानीय मुखिया को निर्देश दिया गया कि विशेष अभियान चलाकर बच्चों को विद्यालय भेजने का प्रयास करें। साथ में अनुमंडल व प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को भी कहा गया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति के हर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने आश्वस्त करवाया की हर लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और बच्चे को स्कूल भेजने के लिए इंप्लीमेंट विशेष अभियान के तहत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा की केंद्र सरकार द्वारा बच्चों को पोशाक, छात्रवृत्ति, मध्यान भोजन उपलब्ध करवाई जा रही है बावजूद आज भी बहुत से इस वर्ग के बच्चे स्कूल से वंचित है उनके बदन पर कपड़े फटे हुए है जिसमें सुधार की जरूरत है साथ ही उन्होंने कहा की नल का जल योजना में नल है लेकिन जल नहीं है फिर ऐसी योजनाओं का क्या लाभ है। उन्होंने यहां की कृषि एवं उनकी उपज, जीविका एवं अन्य आय के इस वर्गों के स्रोतों की जानकारी ली। आगे उन्होंने कहा की हमारे भ्रमण के पश्चात आयोग के अध्यक्ष भी इस वर्ग के विकास के लिए इन क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी वीरपुर कुमार सत्येंद्र यादव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार मिश्रा, आरडीओ कुमार मनीष भारद्वाज, प्रभारी अंचलाधिकारी शशि भास्कर, रोजगार सेवक आमोद आनंद, आवास सहायक विकास भारती, बीआरसी से मनोज कुमार, रतनपुर पंचायत सचिव शिवचंद्र राम, सकलदेव पोद्दार, जयकृष्ण सिंहा, धीरेंद्र मेहता, सुधीर साह, रामदेव मंडल, पंकज मंडल, राजेश मंडल, विनोद यादव समेत पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग मौजूद थे।

सोशल मीडिया से संज्ञान

← Tweet

Vijay Sampla
@thevijaysampla

वीडियो शर्मनाक है।
@RajPoliceHelp इस मामले की पूरी जानकारी एवं की गई कार्यवाही की रिपोर्ट बिना विलंब @NCSC_GoI को भिजवाएं।

Translate Tweet

> Komal karanwal @Komalkaranwal_ · Nov 26
> राजस्थान के सिरोही में जातिवादी लोगों का अत्याचार' दलित इलेक्ट्रिशियन को लाइट फिटिंग के काम के पैसे मांगने पर जमकर पीटा' पेशाब पिलाने और जूतों की माला पहनाकर किया बेज्जत, जातिवादियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल।
> @KhiladiLalINC @SirohiPolice

9:46 PM · Nov 27, 2022

146 Retweets 3 Quote Tweets 357 Likes

श्री मुक्तसर साहिब पहुंचने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुऐ स्थानीय अधिकारी।

भारतीय स्टेट बैंक की एस सी/एस टी कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ सर्किल द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए श्री विजय सांपला जी।

National Commission For Scheduled Castes
5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003